

यू.पी. इन्वेस्टर्स समिट 2018 में हस्ताक्षरित एम.ओ.यू के निवेशकों संग संवाद सत्र
**औद्योगिक विकास मंत्री की अध्यक्षता में द्वितीय ग्राउण्ड ब्रेकिंग
सेरेमनी की दूसरी तैयारी बैठक सम्पन्न**

- अगले दो माहों में एक लाख करोड़ रुपये के निवेश की परियोजनाओं की ग्राउण्ड ब्रेकिंग का लक्ष्य
- दिसम्बर में 50,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं की ग्राउण्ड ब्रेकिंग की तैयारी
- सेवा क्षेत्र हेतु उत्तर प्रदेश की नवीन नीति बनाई जाए

—उद्योग मंत्री, श्री सतीश महाना

- रिटेल की भी नीति शीघ्र लाई जाएगी
- इलेक्ट्रिक वाहन नीति को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए
- प्रदेश में पहली बार विद्युत के ओपन एक्सेस हेतु 340 मेगावॉट क्षमता उपलब्ध कराई गई
- सिंगल विण्डो पोर्टल—निवेश मित्र से फायर सेफ्टी के अनापत्ति—प्रमाण पत्र से संबंधित समस्याओं को शीघ्र दूर कराएं

—मुख्य सचिव व अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, डॉ. अनूप चन्द्र पाण्डेय

लखनऊ, 01 दिसम्बर 2018

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री, श्री सतीश महाना ने कहा है कि अगले दो माहों में एक लाख करोड़ रुपये के निवेश की परियोजनाओं की ग्राउण्ड ब्रेकिंग का लक्ष्य है तथा दिसम्बर में 50,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं की ग्राउण्ड ब्रेकिंग की तैयारी की जा रही है।

मा. मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में सेवा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तर प्रदेश की नवीन नीति बनाई जाएगी, जिससे इस क्षेत्र में होने वाले निवेश से रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे।

औद्योगिक विकास मंत्री आज यहाँ योजना भवन में आयोजित द्वितीय ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी की दूसरी तैयारी बैठक में निवेशकों, उद्योगपतियों एवं अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्य सचिव व अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी), डॉ. अनूप चन्द्र पाण्डेय ने संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों व सचिवों सहित परियोजनाओं के शुभारम्भ (ग्राउण्ड ब्रेकिंग) समारोह से पहले परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक-एक निवेशक के साथ व्यापक वार्ता एवं चर्चा की। आज उन निवेशकों को आमंत्रित किया गया था जिनकी परियोजनाओं को दूसरी ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में सम्मिलित किया जा रहा है।

बैठक के दौरान अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, डॉ अनूप चन्द्र पाण्डेय ने बताया कि राज्य की रिटेल की नीति शीघ्र लाई जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन नीति को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए। उन्होंने बताया कि पहली बार उत्तर प्रदेश में विद्युत के ओपन एक्सेस हेतु 340 मेगावॉट क्षमता उपलब्ध करा दी गई है, जिसका लाभ इच्छुक निवेशक उठा सकते हैं।

डॉ पाण्डेय ने यह भी निर्देश दिए कि बायोफ्यूल क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने वाले निवेशकों को कैपिटल सब्सिडी उपलब्ध कराने से संबंधित प्रकरणों को उ.प्र. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण (यूपीनेडा) शीघ्र निस्तारण करे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सिंगल विण्डो पोर्टल-निवेश मित्र से फायर सेफ्टी के अनापत्ति-प्रमाण पत्र से संबंधित समस्याओं को शीघ्र दूर कराया जाए।

आज जिन निवेशकों ने संवाद-सत्र में प्रतिभाग किया उनमें प्रमुख रूप से ए.बी.ए. इन्फ्राटेक प्रा. लि. आदित्य बिरला ग्रुप, अमरून फूड्स प्रा. लि., सेलेस्टो यार्न, ग्रीनलैम लैमिनेट्स, हाअर इण्डिया, टेकोरेंज मोटरस्पार्ट्स, वेस्टवे इलेक्ट्रॉनिक्स लि. वीवो मोबाइल्स, कनोडिया ग्रुप, के. रिफाइनरी प्रा. लि., सृष्टि इण्डस्ट्रीज़, सुखबीर एग्रो, सन सोर्स इनर्जी, टेरा हैण्डिक्रैफ्ट्स, ऑरगेनिक इण्डिया, शार्क शॉप्स फिट्स प्रा. लि. एसएमसी डेयरीज़ प्रा लि ट्रू पावर अर्थिंग्स प्रा लि, मारकीज़ बायोकेम सहित **लगभग 40 कंपनियों** के वरिष्ठ अधिकारियों ने संवाद में भाग लिया। इन कंपनियों ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का प्रस्ताव दिया है, जैसे- रेल पार्क, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्रोद्योग, जैव-ईंधन, पर्यटन, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, डेयरी, लैमिनेट्स आदि।

अन्य लोगों के अतिरिक्त, प्रमुख सचिव, राजस्व-श्री सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव, ऊर्जा - श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव-वन एवं पर्यावरण-सुश्री कल्पना अवस्थी, प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास-श्री राजेश कुमार सिंह, संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु एवं विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास - श्री अरुण कुमार, विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास-श्री अंकित अग्रवाल इत्यादि ने इस वृहद् बैठक में भाग लिया।

.....